

वर्ष 2023-24 के लिये वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (ASI)

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 के लिये वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (ASI) जारी किया है।

महत्वपूर्ण संकेतक

पैरामीटर	विवरण
GVA वृद्धि	+11.89% (उत्पादन: 5.8% और इनपुट: 4.71% से अधिक) → बेहतर दक्षता
शीर्ष GVA क्षेत्र	मूल धातुएँ, मोटर वाहन, रसायन, खाद्य उत्पाद, फार्मा (उत्पादन का 48%)
शीर्ष 5 GVA राज्य	महाराष्ट्र (16%), गुजरात (14%), तमिलनाडु (10%), कर्नाटक (7%), उत्तर प्रदेश (7%)
रोज़गार वृद्धि	+5.92% वार्षिक; वर्ष 2014-15 से 57 लाख रोज़गार मिले
शीर्ष रोज़गार राज्य	तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक
औसत पारिश्रमिक	5.6% की वृद्धि, हालाँकि GVA वृद्धि दर से कम

अवसर बनाम चुनौतियाँ

अवसर	चुनौतियाँ
औद्योगिक उत्पादन (IIP) वृद्धि (अगस्त 2025), GDP का 17% विनिर्माण से	लॉजिस्टिक्स, बंदरगाहों, विद्युत, भंडारण में बुनियादी ढाँचे की कमी
वर्ष 2024-25 में 81.04 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), विनिर्माण में 18% से अधिक FDI	MSME ऋण अंतराल, उच्च उधारी लागत
प्रमुख क्षेत्रों में आधुनिकीकरण: इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, ऑटो, वस्त्र	कम लागत वाली प्रतिस्पर्धा (चीन, वियतनाम), कमज़ोर अनुसंधान एवं विकास
PLI, GST, PM मित्र, NMM पैमाने और निवेश को बढ़ावा दे रहे हैं	असमान उद्योग 4.0, स्वचालन से संबंधित रोज़गार की आशंकाएँ, गैर-टैरिफ बाधाएँ, बढ़ते टैरिफ
कौशल कार्यक्रम (PMKVY, स्किल इंडिया) रोज़गार सृजन को बढ़ावा दे रहे हैं	केवल 4.7% कार्यबल औपचारिक रूप से प्रशिक्षित
हरित क्षेत्र को बढ़ावा: नवीकरणीय ऊर्जा, शुद्ध-शून्य लक्ष्य	हरित मानकों (CBAM, इथेनॉल मिश्रण) से अनुपालन लागत

औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु प्रमुख उपाय

- औद्योगिक गलियारे और स्मार्ट शहर: कम रसद लागत, निवेश आकर्षित करना।
- मिशन-संचालित विकास: NMM, मेक इन इंडिया, प्रमुख क्षेत्रों के लिये PLI।
- कौशल विकास: PMKVY, तकनीकी तत्परता के लिये क्षेत्रीय कौशल।
- वित्तीय समावेशन और MSME सहायता: ऋण पहुँच, GST रिफंड, नवाचार प्रोत्साहन।
- स्थिरता पर ध्यान: सोलर PV के लिये PLI, हरित हाइड्रोजन मिशन, वृत्ताकार अर्थव्यवस्था।
- व्यापार सुविधा: बेहतर FTA, NTB को कम करना, वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं (जैसे- जापान मॉडल) का अनुकरण करना।

भारत में बेरोज़गारी के जाल का निराकरण

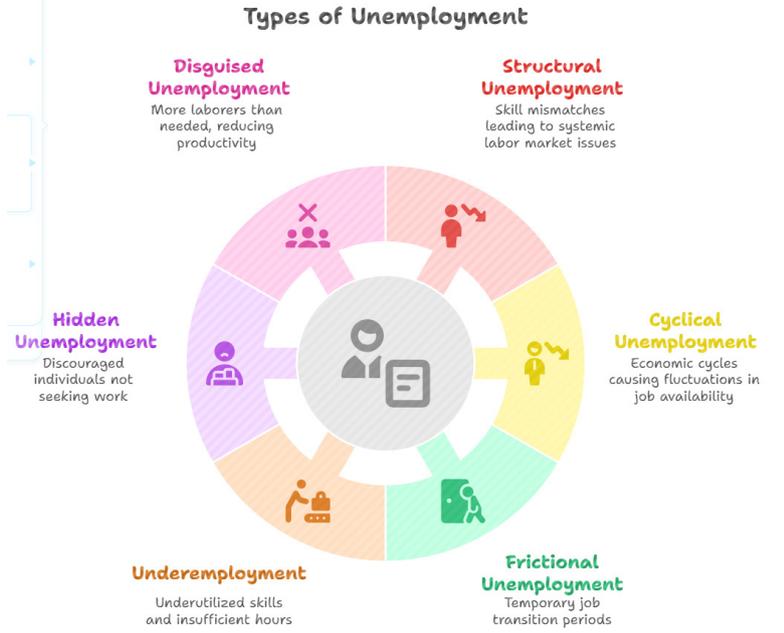
भारत को पर्याप्त रोज़गार सृजित करने के लिये लगभग 12% GDP वृद्धि की आवश्यकता है, हालाँकि RBI ने वित्त वर्ष 2025 के लिये केवल 6.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया है, जिससे विकास-रोज़गार के बीच व्यापक अंतर उजागर होता है।

भारत में बेरोज़गारी की स्थिति

- परिभाषा: बेरोज़गारी = (बेरोज़गार ÷ श्रम बल) × 100
- वर्तमान स्थिति (PLFS 2023-24): कुल मिलाकर 5.1%; युवा (15-29 वर्ष) 14.6%
- ILO 2024: 3 में से 1 युवा बेरोज़गार है।
- वैश्विक संदर्भ: एशिया में युवा बेरोज़गारी 16%; भारत, चीन, इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा प्रभावित।

बेरोज़गारी के कारण

- जनसांख्यिकीय दबाव: नौकरियों में 1.7% की वृद्धि हुई, जबकि कार्यबल में 1.9% (2000-23)।
- कौशल बेमेल: केवल 4.7% औपचारिक रूप से प्रशिक्षित, शिक्षा उद्योग के लिये तैयार नहीं।
- बेरोज़गारी वृद्धि: 6.5-7.8% सकल घरेलू उत्पाद, लेकिन कमज़ोर रोज़गार सृजन;
- निर्यात वैश्विक हिस्सेदारी केवल 1.8%
- शिक्षित बेरोज़गारी: व्हाइट-कॉलर जॉब्स को प्राथमिकता।
- लैंगिक असमानता: शहरी महिला युवा बेरोज़गारी 25.7% बनाम पुरुष 15.6%
- तकनीकी व्यवधान: कृत्रिम बुद्धिमत्ता/स्वचालन 69% नौकरियों के लिये खतरा बन सकता है (विश्व बैंक)।
- कृषि पर निर्भरता: 45.7% कार्यबल कम वेतन वाली मौसमी कृषि नौकरियों में → ग्रामीण अल्परोज़गार।



प्रभाव	आवश्यक सुधार
आर्थिक नुकसान: कम GDP, कमज़ोर मांग	श्रम-प्रधान विनिर्माण को बढ़ावा: वस्त्र, चमड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक्स
गरीबी और असमानता: बढ़ती असमानता	कौशल की खाई पाटना: AI, IoT, डेटा विश्लेषण; पुनः कौशल विकास का विस्तार
सामाजिक अस्थिरता: अपराध, अशांति, अलगाव	MSME और स्टार्टअप को समर्थन: ऋण, अनुपालन में आसानी, VC पारिस्थितिकी
मानसिक स्वास्थ्य संकट: तनाव, कौशलहीनता	कृषि विविधीकरण: कृषि उद्योग, मत्स्य पालन, पशुपालन
राजकोषीय दबाव: उच्च कल्याण, कम कर राजस्व	सार्वजनिक निवेश: बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा; नौकरियों के लिये PLI योजनाओं का लाभ उठाना

भारत में खाद्यान्न भंडारण

भारत ने वर्ष 2024-25 के लिये 353.96 मिलियन टन का रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन प्राप्त किया है।

60-70% उपज घरेलू स्तर पर स्वदेशी तरीकों (मोरई, मड कोठी) के माध्यम से संग्रहीत की जाती है।

वर्तमान भंडारण प्रणाली

एजेंसी/संस्था	भूमिका
FCI	साइलो, गोदामों और CAP संरचनाओं के साथ लगभग 917.83 लाख मीट्रिक टन क्षमता का प्रबंधन करता है।
CWC & SWCs	कृषि उपज का भंडारण; वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन अधिनियम के तहत संचालित।
निजी एजेंसियाँ	अतिरिक्त भंडारण हेतु अभिवहन क्षमता।
WDRA, रेलवे, नागरिक आपूर्ति	अनाज के आवागमन और विनियमन में प्रमुख सहायक।

भंडारण का महत्त्व

- नुकसान कम होता है: अनाज की गुणवत्ता और मात्रा अनुरक्षित रहती है।
- बफर स्टॉक सुनिश्चित होता है: सार्वजनिक वितरण प्रणाली और आपात स्थिति में।
- मूल्य स्थिरीकरण: मौसमी मूल्य गिरावट को रोकता है।
- किसान आय सहायता: विलंबित, लाभदायक बिक्री को सक्षम बनाता है।
- खाद्य प्रसंस्करण और निर्यात को बढ़ावा देता है।

महत्त्वपूर्ण पहलें

योजना	उद्देश्य
AIF (2020)	फसलोत्तर बुनियादी ढाँचे के लिये ब्याज अनुदान सहित ऋण वित्तपोषण।
AMI (ISAM घटक)	ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता।
PMKSY	खाद्य प्रसंस्करण के लिये बुनियादी ढाँचा; अपव्यय कम करता है, आय/निर्यात को बढ़ावा देता है।
स्टील साइलो निर्माण	आधुनिक भंडारण विस्तार।
PEG स्कीम	रोज़गार की गारंटी के साथ भंडारण में निज़ी निवेश।
स्टोरेज एवं गोडाउन स्कीम	पूर्वोत्तर, जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों पर केंद्रित।

चुनौतियाँ और उपाय

चुनौतियाँ	उपाय
22% खाद्यान्न हानि (लगभग 74 मीट्रिक टन/वर्ष)	वैज्ञानिक भंडारण का विस्तार (उदाहरण के लिये बिहार का 50,000 मीट्रिक टन साइलो)
कीट/आर्द्रता से 6.58% हानि	कटाई के बाद बेहतर प्रबंधन, शुष्कन और सफाई
₹7,000 करोड़/वर्ष की हानि (कीटों से ₹1,300 करोड़)	सार्वजनिक निज़ी भागीदारी (PPP) को बढ़ावा देना, रोज़गार की गारंटी के साथ PEG को मज़बूत करना।
90% गेहूँ CAP के अंतर्गत संग्रहीत (उदाहरण के लिये, पंजाब)	लगभग 63,000 इकाईयों के कंप्यूटरीकरण के माध्यम से PACS को सशक्त बनाना
पूर्वोत्तर, जनजातीय, पहाड़ी क्षेत्रों में क्षेत्रीय अंतर	बुनियादी ढाँचे की कमी को दूर करने के लिये लक्षित योजनाएँ

अमेज़न वर्षावन

एक अध्ययन में पाया गया है कि बढ़ते CO₂ स्तर के कारण अमेज़न के वृक्ष बड़े हो रहे हैं, जिससे कार्बन निषेचन प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। इसके परिणामस्वरूप प्रकाश संश्लेषण, पौधों की वृद्धि और कार्बन भंडारण में वृद्धि देखने को मिलती है।

कार्बन निषेचन प्रभाव

- उच्च CO₂ → अधिक प्रकाश संश्लेषण → पौधों की तेज़ वृद्धि, जैवभार में वृद्धि।
- पौधों की जल क्षमता में सुधार।
- सीमाएँ: प्रभावित जल, पोषक तत्वों (विशेषकर नाइट्रोजन) और तापमान पर निर्भर करता है।

अमेज़न वर्षावन (सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन)

विशेषता	विवरण
स्थान	दक्षिण अमेरिका; लगभग 60 लाख वर्ग किमी में फैला; 60% ब्राज़ील में। पेरू, कोलंबिया, वेनेज़ुएला, इक्वाडोर, बोलीविया, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना में फैला हुआ।
सीमाएँ	गुयाना हाइलैंड्स (उत्तर), एंडीज़ (पश्चिम), ब्राज़ीलियाई पठार (दक्षिण), अटलांटिक (पूर्व)
जैव-विविधता	विश्व की 10% प्रजातियाँ पाई जाती हैं; समृद्ध वनस्पति और जीव-जंतु
वनस्पति और जीव-जंतु	रबर का वृक्ष, ब्राज़ील नट, महोगनी, देवदार, शीशम, ताड़ और जगुआर, मैनाटी, कैपीबारा, एनाकोंडा, स्लोथ, मैकॉ
संरक्षित क्षेत्र	यासुनी (इक्वाडोर), मनु (पेरू), जौ और तुमुकुमाके (ब्राज़ील), आदि।
वैश्विक भूमिका	'पृथ्वी के फेफड़े' - वैश्विक ऑक्सीजन का 20%, प्रमुख कार्बन सिंक

अमेज़न नदी

- निर्वहन के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी, विश्व स्तर पर दूसरी सबसे लंबी
- स्रोत: पेरूवियन एंडीज़ → अटलांटिक महासागर में प्रवाहित
- सहायक नदियाँ: रियो नीग्रो, मदीरा, ज़िंगु
- जलग्रहण क्षेत्र: ब्राज़ील, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेज़ुएला, बोलीविया

महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती

2 अक्तूबर को महात्मा गांधी (1869-1948) और लाल बहादुर शास्त्री (1904-1966) की जयंती मनाई गई।

महात्मा गांधी	लाल बहादुर शास्त्री
<ul style="list-style-type: none"> जन्म: 2 अक्तूबर, 1869, पोरबंदर; इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई की। 	<ul style="list-style-type: none"> प्रारंभिक जीवन: मुगलसराय में जन्म; काशी विद्यापीठ से 'शास्त्री' की उपाधि प्राप्त की।
<ul style="list-style-type: none"> दक्षिण अफ्रीका (1893-1914): पीटरमैरिटज़बर्ग में नस्लीय भेदभाव, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना, इंडियन ओपिनियन, फीनिक्स समझौता, टॉल्स्टॉय फार्म → विकसित सत्याग्रह 	<ul style="list-style-type: none"> स्वतंत्रता संग्राम: CDM में सक्रिय; 7+ वर्ष जेल में रहे।
<ul style="list-style-type: none"> भारत वापसी: 9 जनवरी, 1915 (प्रवासी भारतीय दिवस); साबरमती आश्रम की स्थापना की। आंदोलन: चंपारण (1917), खेड़ा (1918), टौलट (1919), NCM (1920), CDM (1930), QIM (1942) 	<ul style="list-style-type: none"> राजनीतिक जीवन: उत्तर प्रदेश संसदीय सचिव (1946); केंद्रीय मंत्री (रेल, गृह, आदि)। 1956 की रेल दुर्घटना (नैतिक ज़िम्मेदारी) के बाद इस्तीफा दे दिया।
<ul style="list-style-type: none"> विचार एवं लेखन: हिंद स्वराज, खादी और चरखे का प्रचार किया। संस्थाएँ: ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन (1925), हरिजन सेवक संघ (1932) 	<ul style="list-style-type: none"> प्रधानमंत्री (1964-66): 1965 के भारत-पाक युद्ध के दौरान, "जय जवान, जय किसान" का नारा दिया।
<ul style="list-style-type: none"> मृत्यु: 30 जनवरी, 1948 को हत्या। विरासत: 2 अक्तूबर = गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस (संयुक्त राष्ट्र, 2007) 	<ul style="list-style-type: none"> मृत्यु: ताशकंद घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद ताशकंद में (11 जनवरी, 1966) निधन हो गया।

वर्तमान पहलों में गांधीवादी दर्शन

- स्वच्छ भारत → स्वच्छता
- स्वयं सहायता समूह → सहकारी अर्थशास्त्र
- खादी एवं ग्रामोद्योग → स्वदेशी
- स्वामित्व योजना → ग्राम स्वावलंबन
- मनरेगा → काम करने का अधिकार

पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (MLAT)

- परिभाषा: आपराधिक मामलों (आतंकवाद, तस्करी, साइबर अपराध, धोखाधड़ी) में सहयोग के लिये द्विपक्षीय/बहुपक्षीय संधियाँ।
- उद्देश्य: साक्ष्य साझा करना, जाँच, अभियोजन → क्षेत्राधिकार संबंधी कमियों के माध्यम से अपराधियों के बच निकलने को रोकना।
- महत्त्व: अंतर्राष्ट्रीय अपराधों में पारस्परिकता, गति और मज़बूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सुनिश्चित करती है।
- भारत का दृष्टिकोण:
 - विदेश मंत्रालय के सहयोग से गृह मंत्रालय (MHA) के माध्यम से MLA अनुरोध भेजे जाते हैं।
 - भारत ने 42 देशों (2019) के साथ MLAT पर हस्ताक्षर किये हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (भारत का हिस्सा):

- अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (2000)
- भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (2003)
- मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (1988 - वियना सम्मेलन)
- हेग सम्मेलन
- सार्क सम्मेलन
- कॉमनवेल्थ हरारे स्कीम

इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैनुफैक्चरिंग स्कीम (ECMS)

अप्रैल 2025 में प्रारंभ हुए ECMS ने 13 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश प्रस्ताव (लक्ष्य से दोगुना) आकर्षित किये हैं, जिसमें 60% MSME भागीदारी और 1.41 लाख रोज़गार सृजन का लक्ष्य है।

- लॉन्च: इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को पूरक बनाने के लिये।
- अवधि: 6 वर्ष (वित्त वर्ष 2025-26 से 2031-32; 1 वर्ष की स्थापना अवधि शामिल है)
- उद्देश्य: घरेलू मूल्य संवर्द्धन को बढ़ावा देना, आयात में कटौती करना, वैश्विक मूल्य शृंखलाओं के साथ एकीकरण करना।
- लिंकेज: इलेक्ट्रॉनिकी + ऑटोमोबाइल, विद्युत, औद्योगिक क्षेत्र
- प्रोत्साहन: टर्नओवर-लिंकड, कैपेक्स-लिंकड, या हाइब्रिड; आंशिक रूप से रोज़गार सृजन से संबंधित; पहले आओ, पहले पाओ।
- महत्त्व:
 - इलेक्ट्रॉनिकी = भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात; दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता।
 - लक्ष्य: वर्ष 2030-31 तक 500 अरब अमेरिकी डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम।